

## स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन

प्रा.कु.वि.एम.दे वकर

गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

कला वाणज्य महिला महाविद्यालय, बल्लारपुर

### प्रस्तावना:

कसी भी व्यवसाय को शुरू करने हेतु धन की आवश्यकता होती है। यदि एक महिला उद्यमी कसी व्यवसाय को चुनती है, तो उसे शुरू करने से पहले उसकी जरूरत की पूंजी को समायोजित करना होगा। इसके लिए, गृहिणी को यह जानने की आवश्यकता होती है कि पूंजी कैसे प्राप्त की जाए, कससे की जाए। एक छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के कई तरीके हैं। जिसमें पूंजी उसके द्वारा उठाए गए धन, परिवार द्वारा उठाए गए धन, गृहिणी द्वारा बचाए गए धन के माध्यम से जुटाई जाती है। उद्यमी अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से पैसे जुटा सकता है। इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। यह पैसा उद्योग शुरू होने पर कए गए मुनाफे से चुकाया जाता है।

कई वित्तीय संस्थान अचल संपत्तियों के लिए दीर्घकालक ऋण प्रदान करते हैं। उद्योग के लिए भूमि खरीदने के लिए, आवश्यक उपकरणों की खरीद, उद्योग के लिए निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस ऋण की अवधि 5 से 10 वर्ष होती है। ऋण को 3 महीने की निश्चित कशतों में चुकाना होता है। टर्म लोन उद्योग विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य निवेश निगम और वाणज्यिक बैंक भी प्रदान करते हैं। इसकी पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्ष है। ऋण से उत्पन्न संपत्ति को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है। इस राशि का 75% उधार लिया जा सकता है।

राज्य सरकार की निधि या कुछ संबद्ध एजेंसियां कशतों पर मशीनरी की आपूर्ति करती हैं। हुंडी का उपयोग उद्योग के लिए पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। वाणज्यिक बैंक और नागरिक सहकारी बैंक केवल कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं। जो ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऋण की राशि के अनुसार ब्याज दरें बढ़ती हैं। ऋण वर्ष के अंत में नवीनीकृत किया जाता है। स्वरोजगार हेतु अनेक संस्थाएँ ऋण प्रदान करती हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना है।

अनुसंधान निबंध के लिए प्रयुक्त अनुसंधान विधि:

वर्तमान शोध प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संकलित किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- 1) स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
- 2) स्वरोजगार हेतु ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यों को जानना।

- 3) महिलाओं के विकास और युवा बेरोजगारी को कम करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
- 4) अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्वरोजगार के विकास हेतु उपाय सुझाना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

उदारीकरण की शुरुआत, इसकी वक सत प्रकृति और अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के साथ, भारत में वैश्विक विकास ने न केवल उन मानकीकृत संस्थानों की स्थापना की है, बल्कि अपने काम का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। चूंकि पारंपरिक वृत्तीय प्रणाली सभी के लाभ तक नहीं पहुंची है, इस लए कई वृत्तीय संस्थानों ने अपनी वृत्तीय जरूरतों को पूरा करने के लए महत्वपूर्ण बदलाव कए हैं और आज माइक्रोफाइनेंस से संबंधित अधिकांश वृत्तीय जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इन संस्थानों के मुख्य सेवा वर्ग वे हैं जिनकी अभी तक बैंक सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इन वृत्तीय सेवाओं को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वनियमत किया जाता है। हालांकि, इसके वनियमन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

देश के कुछ राज्यों में वक सत स्व-सहायता समूहों ने स्वरोजगार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पछले दो दशकों में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और बैंक संस्थानों द्वारा सुवधा और विकास के लए पर्याप्त कार्य किया गया है। मैदान में। इन सबका एकमात्र उद्देश्य देश में गरीबों को वृत्तीय सुवधाएं प्रदान करना है। स्वरोजगार के विकास में इन संगठनों की भूमिका जानने के लए, उनके कार्य का अध्ययन करना आवश्यक है।

स्वरोजगार का अर्थ:

एक स्व-नियोजित व्यक्ति को एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने लाभ के लए व्यावसायिक या व्यावसायिक गतिवधियों का संचालन करता है। दूसरे शब्दों में, इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है जो अपनी ओर से काम करता है और सीधे कसी तीसरे पक्ष द्वारा काम पर नहीं रखा जाता है।

स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भूमिका:

उद्योग के लए आवश्यक भूमि की खरीद मूल्य, कानूनी शुल्क, भूमि समतल करना, सड़कें, आंतरिक सड़कें, बाड़, चयनित व्यवसाय के अनुसार आवश्यक निर्माण करना, मशीनरी और उपकरण खरीदना बिजली और पानी की उपलब्धता की लागत, प्रारंभिक उत्पादन से पहले केवल एक बार वहन करना पड़ता है। प्राथमिक और पूर्व-उत्पादन लागत में उद्योग पंजीकरण लागत, परियोजना रिपोर्ट, यात्रा व्यय, ब्याज ऋण, निर्माण लागत आदि शामिल हैं। वकैंग कैपटल को प्रंसपल कैपटल कहा जाता है। ऐसा इस लए है क्योंकि "कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जिसका उपयोग कसी व्यवसाय को चलाने या उद्योग को चलाने के लए किया जाता है।" बाजार में तैयार माल बेचने के लए कच्चे माल को खरीदने की लागत को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उद्योग शुरू करने के बाद कच्चे माल की जरूरत होती है। इन वस्तुओं की मात्रा उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। संग्रह क्षमता, कच्चे माल का प्रकार, उनका संग्रह सभी पूंजी से निकटता से संबंधित हैं। उत्पादन में वृद्धि से व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि से पूंजी में वृद्धि होती है। कन्तु ये बात भी सत्य है कि

पूंजी के बिना व्यवसाय क शुरुवात ही नहीं होती। स्वरोजगार हेतु पूंजी एक बड़ा प्रश्न है। भारत में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु व भन्न संस्थाए उद्य मयों को वत्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जो निम्नप्रकार के हैं: स्वरोजगार के लए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएँ:

(1) महाराष्ट्र राज्य वत्तीय निगम (M.S.E.C.): - इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बोर्ड भूम, मशीनरी, उपकरण और स्थायी संपत्ति के अधग्रहण के लए लघु और मध्यम उद्यमों को दीर्घकालक ऋण प्रदान करता है। इसके द्वारा महिला उद्य मयों को वत्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों को अपनी लागत के 12.5% पर वत्तपोषत कया जाता है। महिला उद्यम कोष के तहत, बोर्ड अपनी पूंजी पर वत्तीय सहायता प्रदान करता है। उधार देने वाला वत्त बोर्ड माल क खरीद, होटल व्यवसाय, खाद्य संरक्षण, वाहन मरम्मत, कूलर खरेदी आदि हेतु वत्तीय सहायता प्रदान करता है। कई छोटे व्यवसायों के लए दीर्घकालक ऋण की पेशकश भी करता है। घरेलू सामान, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, कपड़े धोने, सजावट, मंडप निर्माण के लए सेवा उद्य मयों के लए दीर्घकालक ऋण भी उपलब्ध कया जाता है।

उद्य मयों को स्थिर ऋण प्रदान करने के लए राज्य वत्त बोर्ड का गठन कया गया है। वनिर्माण, होटल व्यवसाय, मरम्मत और कूलर के निर्माण, वाहन की मरम्मत, प्रसंस्करण परियोजनाओं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों जैसे व्यवसायों के लए राज्य वत्त बोर्ड से टर्म लोन प्राप्त कया जा सकता है। सेवा उद्योग के लए राज्य वत्त बोर्ड द्वारा टर्म लोन प्रदान कया जाता है। जैसे दूरसंचार मरम्मत, यात्री सेवा, वीडियो रिकॉर्डिंग, गैस स्टोव मरम्मत, कपड़े धोने का व्यवसाय, सजावट मंडप निर्माण, एयर कंडीशनिंग मरम्मत आदि।

(2) भारत का औद्योगिक विकास कोष: - इस कोष द्वारा उद्योगों को वत्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्गीकृत कया जाता है। यह स्व-रोजगार को बढ़ावा देने वाले संगठनों में से एक है। स्वरोजगार के लए, पछड़े क्षेत्रों में सेवा उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। ऋण रियायती ब्याज दर पर वत्तपोषत होता है और ब्याज भुगतान की सुवधा होती है। अतः पुनर्भुगतान सुवधाजनक हो सकता है, साथ ही पुनर्भुगतान अवध अन्य संस्थानों की तुलना में लंबी होती है। यह संस्था दीर्घकालक ऋण भी प्रदान करती है। इस लए, दीर्घकालक विकास के लए धन प्रदान करने की जिम्मेदारी इस निध पर रखी गई है।

(i) इंडस्ट्रियल रिफाइनेंग संग कर्पोरेशन ऑफ इंडिया: - इंडस्ट्रियल रिफाइनेंग संग कर्पोरेशन ऑफ इंडिया उधार देने वाली संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य लघु और मध्यम अवध के ऋण प्रदान करना है।

(ii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया: - यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 से कार्य कर रही है। यह छोटे और मध्यम स्वरोजगार करने वालों को वत्त प्रदान करता है। योजना निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बचत करने के लए प्रोत्साहित करती है, उनकी बचत एकत्र करती है और उन्हें वत्त देती है। इतना ही नहीं, निवेशकों को यूनिट धारकों को 90% शेयर आवंटित कए जाते हैं। यह योजना इकाइयों और वत्तपोषण उद्योगों की खरीद से लाभान्वित होने वाली आम जनता के साथ लोकप्रिय हो गई है।

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम: - यह वत्त प्रदान करने वाला एक वश्वसनीय निगम है। मुख्य रूप से आवास के लए और स्वरोजगार के लए ऋण प्रदान करता है। इसमें दीर्घकालक ऋण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा पुनर्भुगतान की कश्तें आसान हैं। चुकौती अवध भी लंबी है।

(iv) औद्योगिक विकास निगम: - यह संगठन स्वरोजगार के लिए वत्त प्रदान करता है। जिला स्तर पर, जिला उद्योग अधिकारी परियोजना मॉडल को मंजूरी देता है और निगम को ऋण के रूप में परियोजना के लिए आवश्यक धन का संवतरण करने की सफारिश करता है। व्यापारी द्वारा अनुरोध की गई ऋण राशि का 25% निवेश करना आवश्यक है। इस निवेश को किए बिना 75% राशि का भुगतान उधारकर्ता को नहीं किया जाता है।

(v) मर्चेट फंड: - जिला उद्योग केंद्र की सफारिश के अनुसार, व्यापारी ऋण के रूप में लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। 10% पूंजी व्यवसायी को स्वयं जुटानी पड़ती है। पूंजी का 90% मर्चेट फंड द्वारा उधार दिया जाता है। इसके अलावा, इसकी ब्याज दर अन्य संस्थानों की तुलना में अधिक है और पुनर्भुगतान की अवधि कम है। सरकारी नियमों के अनुसार, असुरक्षित ऋण स्वरोजगार को दिया जाना चाहिए। लेकिन मर्चेट फंड इस मामले में उदासीन हैं।

(vi) सवाल कोऑपरेटिव फंड: - सवाल कोऑपरेटिव फंड स्वरोजगार के लिए उद्यमियों को बड़ी मात्रा में ऋण सहायता प्रदान करता है। उनकी ब्याज दरें वाणिज्यिक अधिशेष से कम हैं। चुकौती अवधि भी लंबी है। इसके अलावा, इसकी चुकौती सुविधाओं को भी सरल बनाया गया है। इस लिए यह आजकल अधिक लोकप्रिय है। इस वित्तीय संस्थान की अलग-अलग योजनाएँ हैं। इनमें निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं: (1) महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजना (2) रेस्तरां वित्तीय सहायता योजना (3) वाहन खरीद वित्तीय सहायता योजना (4) सेवा उद्योग वित्तीय सहायता योजना (5) अस्पताल और नर्सिंग होम वित्तीय सहायता योजना (6) पर्यटन विकास वित्तीय सहायता योजना (7) मशीनरी वित्तीय सहायता योजना (8) आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना (9) भूतपूर्व सैनिक वित्तीय सहायता योजना (10) सामान्य ऋण योजना (11) योग्य पेशेवरों के लिए वित्तीय सहायता योजना व भन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है।

महिलाओं के विकास और युवा बेरोजगारी को कम करने के लिए अन्य योजनाएँ:

(1) महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना के तहत व्यक्तिगत सहायता: -

यह योजना महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी या कम रोजगार के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसी महिलाओं को परिपक्व, पीड़ित, वधवा, सामाजिक-जातीय रूप से शोषित, आर्थिक रूप से पछड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय मदद से महिलाओं को सलाई (ड्रेस डिजाइनिंग), कढ़ाई, मछली, सब्जी, भोजन तैयार करने और बेचने, खलौने बनाने, पेपर बैग बनाने, पैकंग के लिए प्लास्टिक बैग बनाने जैसे स्वरोजगार के लिए ऋण मिल सकता है। इस ऋण के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है।

(2) शक्ति बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना: -

आज की स्थिति में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से युवाओं के लिए एक स्वरोजगार योजना वकसत की है। इस योजना के तहत, लघु व्यवसाय या सेवा उद्योग को ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जेरोक्स मशीनों, आटा मलों, गैरेज, रेडीमेड कपड़ों, फास्ट फूड में निवेश करके पुरुषों और महिलाओं को स्वरोजगार के

लए ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी चुकौती अवध लंबी होती है। इस प्रकार, स्वरोजगार के लिए, व भन्न वत्तीय संस्थान इन ऋणों को चुकाकर बेरोजगारी को कम करने में मदद करते हैं।

अन्य स्व-रोजगार वत्तपोषण योजनाएं:

(१) प्रधान मंत्री रोजगार योजना: - यह योजना २ अक्टूबर 1993 को महात्मा गांधी की जयंती से लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने शक्ति बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1993 से एक स्वरोजगार ऋण योजना शुरू की है। नेशनल बैंक के माध्यम से किसी भी व्यवसाय के लिए 1 से 2 लाख रुपये इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है। योजना को छोटे प्रभागों के साथ-साथ जिले में भी लागू किया गया है। इसमें 1) उम्मीदवार के पास कम से कम **S.S.C.** पास या फेल या आई.टी.आई. या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स पास करने का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। 2) आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 3) आवेदक की अपनी पूंजी 5% होनी चाहिए। 4) परिवार की संयुक्त आय रु 40,000 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें एक या अधिक शक्ति बेरोजगार एक साथ आकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

(2) जिला उद्योग केंद्र ऋण (सीड कैप्टल स्कीम): - लघु उद्योग जिन्होंने 2 लाख रुपये तक की मशीनरी में निवेश किया है, वे सीड कैप्टल के रूप में 20 या 30% अचल संपत्तियों (पछड़े वर्ग के लिए) के रूप में ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमियों का निवेश 5% होना चाहिए। इस योजना के तहत, अधिकतम 40,000 रुपये तक की बीज पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है। यदि उद्यम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे 30% का ऋण मिल सकता है, लेकिन अधिकतम 60,000 रुपये तक।

(3) हस्त शिल्प विकास योजना: - केंद्र सरकार ने भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड की स्थापना की है। महाराष्ट्र राज्य निदेशालय और महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम हस्तकला विकास में हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। जैसे पारंपरिक कला में धातु का काम, पत्थर पर नक्काशी, लाख का काम, बोर्ड बनाना, कलाकृति आदि। अपरंपरागत हस्त शिल्प, कढ़ाई, गुड़िया और खलौने, हथकरघा दीवार की लटकन, कांच के खलौने आदि के व्यवसाय हेतु भी ऋण दिया जाता है।

(४) महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड: - यह 1962 में स्थापित किया गया था। यह ग्रामीण कारीगरों, उद्यमियों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है जो छोटे उद्योगों को शुरू करने, अपने उद्योगों को स्थायित्व देने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के इच्छुक हैं। इस बोर्ड में 114 उद्योग शामिल हैं। इसमें महिलाओं के लिए कई व्यवसाय भी शामिल हैं। जैसे: पापड़, कुरदया, अचार, तरल मसाले, सुपारी, मोमबत्तियाँ, चाक बनाना, फनाइल, साबुन, डटर्जेंट पाउडर, बेकरी, उद्योग, संधैतिक सरप आदि का उद्योग कर सकते हैं। यह 1 लाख रुपये तक की वत्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन संस्थाओं के अलावा महात्मा फुले पछड़ा वर्ग विकास निगम, महिला आर्थिक विकास निगम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs), आदि संस्थान स्वरोजगार के लिए वत्त पोषण कर रहे हैं।

बैंकों की भूमिका :

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रयान्वयन में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह ऋण एवं अनुदान कार्यक्रम है, इसमें ऋण एक महत्त्वपूर्ण तत्व है और अनुदान गौण, इस लिए कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में बैंकों के गहरे सहयोग की आवश्यकता होती है। समूह (cluster), प्रमुख कार्यकलापों एवं बुनियादी सुविधाओं के मयों की पहचान करने, परियोजना रिपोर्ट तैयार

करने तथा जिले में कार्यरत कार्यान्वयन के सभी पक्षों की जाँच के लिए बैंक खंड/जिला स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स मतियों की सहायता हेतु आयोजन में शामिल होते हैं। स्वयं-सहायता समूहों के साथ यथा-संभव नजदीकी संबंध बनाए रखना, समूहों के प्रबंधन तथा योजना के अधीन स्व-रोजगार के अवसरों के बारे में उपर्युक्त जागरूकता पैदा करना, स्वयं-सहायता समूहों का बचत खाता खोलना तथा समूहों की सूक्ष्म ऋण की गति व धर्यों (बचत, आंतरिक ऋण और वसू लयाँ) की प्रगति पर नजर रखना , स्वयं सहायता समूहों की क्षमता बढने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना, स्वरोजगारियों के चयन के लिए खंड विकास अधिकारी और सरपंच के साथ तीन सदस्यीय दल के सदस्य के रूप में ग्राम सभाओं में भाग लेना, समूहों के वर्गीकरण प्रक्रिया (**grading exercise**) के बाद उचित पाए गए समूहों को परिक्रामी नि ध सहायता (**Revolving fund assistance**) प्रदान करना, प्रमुख कार्यकलापों के अधीन तैयार कये गये परियोजना रिपोर्ट में इकाई लागत, प्रस्ता वत उद्यम के वत्तमान तथा स्व-रोजगारियों की कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए स्व-रोजगारियों की ऋण आवश्यकता का आकलन करना, द्वितीय वर्गीकरण परीक्षा (**Second grading test**) के बाद उचित पाए गए समूहों को छोटे उद्यम स्था पत करने हेतु वत्तीय सहायता हेतु ऋण-व-अनुदान (**Loan-cum-subsidy**) प्रदान करना, समय पर ऋण (15 दिन के भीतर कंतु कसी भी स्थिति में एक महीने से अधिक नहीं) की स्वीकृति देना ता क स्वरोजगारियों को आवश्यक ऋण उपलब्ध हो सके आदि कार्य बैंक द्वारा स्वरोजगार के विकास हेतु कए जाते हैं। इसी तरह ऋण प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करना क स्वरोजगारी को तकनीकी व प्रबंधन कौशल के मामले में न्यूनतम आवश्यक कुशलता (**Minimum Skill Requirement**) प्राप्त है या नहीं यह जानना, प्र शक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधन कुशलता प्रदान करने के लिए एक अभिज्ञानी व्यक्ति (**Resource person**) की भूमिका निभाना, योजना के अधीन वत्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी नियम व शर्तें तथा ऋण की अदायगी शीघ्र करने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की जानकारी सभी स्व-रोजगारियों को प्रदान करने के लिए आधार-स्तरीय प्र शक्षण कार्यक्रम में सक्रय रूप से भाग लेना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अधीन निर्धारित प्रतिबद्धता का पालन करना, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर ब्याज की दरें, ऋण की अव ध, नकद सं वतरण, चरण-वार सं वतरण, जमानत संबंधी मानदंडों आदि ऋण प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के साथ मल कर आस्तियों की भौतिक जाँच करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके क स्वरोजगारी अच्छी गुणवत्ता वाले आस्तियों का अधग्रहण करता है। स्वरोजगारियों को आवश्यकतानुसार बार-बार ऋण प्रदान करना ता क वे अपने कामकाज का वस्तार कर सके । आदि कार्य बैंक द्वारा स्वरोजगार के विकास हेतु कए जाते हैं। इस प्रकार स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष :

स्वरोजगार के विकास में ऋण देने वाली संस्थाये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रयान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने श क्त बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाए कार्यान्वित क हैं। कन्तु इन से लाभान्वित होने वालो क संख्या अब भी बहोत कम है। योजनाओं क शर्तें जटिल होने के कारण इनका लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पाहुच पा रहा है।

संदर्भ सूची :

- 1) Jennifer Mcknight Trontz, Home Economics: Vintage Advice and Practical Science for the 21st-Century Household, Quirk Books publisher, July 1, 2010
- 2) Ela R. Bhatt, We Are Poor but So Many: The Story of Self-Employed Women in India, Oxford University Press, 2005
- 3) भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. घाटणे व वावरे, निराली प्रकाशन, पुणे, जुलाई- 2010
- 4) भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. स. श्री. मु. देसाई, डॉ. निर्मला भालेराव, निराली प्रकाशन, पुणे, 2 रा संस्करण

वर्तमानपत्र : नवभारत, लोकमत, टाईम्स ऑफ इंडिया

वेबसाइट :

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment>
- <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE>
- <https://www.rbi.org.in/>